भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 307

02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग

307. श्री प्रदीप पुरोहित :

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि ओडिशा के बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के कतिपय भागों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग की सूचना मिली है, जिससे हीराकुड कमान क्षेत्र में मिट्टी की उर्वरता और जल की गुणवत्ता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इन जिलों में मिट्टी के पोषक असंतुलन, नाइट्रेट प्रदूषण या भूजल संदूषण की सीमा का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है या प्रायोजित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त जिलों में किसानों को उचित उर्वरक उपयोग, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा परीक्षण के बारे में शिक्षित करने के लिए कोई जागरूकता या क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार रासायनिक निर्भरता को कम करने के लिए पश्चिमी ओडिशा में और विशेषकर उपरोक्त जिलों में जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट योजनाएँ कार्यान्वित कर रही है; और

(ड.) बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों में अत्यधिक उर्वरक उपयोग की समस्या के समाधान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): ओडिशा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के कुछ क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के संबंध में अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैजिससे हीराकुड कमान क्षेत्र में मृदा की उर्वरता और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है।

वर्ष 2024-25 की मृदा नमूना विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, दोनों जिलों के **पोषक तत्व** सूचकांक निम्नानुसार हैं:-

जिला	उपलब्ध नाइट्रोजन	उपलब्ध P_2O_5	उपलब्ध K_2O	टिप्पणी
बरगढ़	1.16 (एल)	2.43 (एम)	2.38 (एम)	एल: कम,
झारसुगुड़ा	1.11 (एल)	2.37 (एम)	2.56 (एम)	एम: मध्यम,

दोनों जिलों की मृदा की उर्वरता की स्थिति में नाइट्रोजन की मात्रा कम, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा मध्यम बताई गई है। तदनुसार, क्षेत्र की मृदा में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व नहीं हैं। दोनों जिलों के सभी ब्लॉक में मृदा स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए नियमित रूप से मृदा परीक्षण किया जाता है। सॉयलहैल्थ एवं फर्टीलिटी स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान बरगढ़ में 5576 सॉयल हैल्थ कार्ड(एसएचसी) और झारसुगुड़ा में 1952 सॉयल हैल्थ कार्ड (एसएचसी) बनाए गए हैं। इसी प्रकार, पिछले वर्ष, 2024-25 के दौरान, बरगढ़ में 28,824 सॉयल हैल्थ कार्ड (एसएचसी) और झारसुगुड़ा में 4373 सॉयल हैल्थ कार्ड (एसएचसी) बनाए गए थे।

(ग): जी हां, किसानों को उर्वरक के विवेकपूर्ण उपयोग, संतुलित पोषण प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन इत्यादि के बारे में शिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से कई पहल की गई हैं। सॉयल हैल्थ कार्ड, उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन इत्यादि के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए हर वर्ष ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, मृदा स्वास्थ्य पर ओडिशा के सभी 314 ब्लॉक में ऐसे 1350 जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही "धरतीमाता बचाओ अभियान" के तहत, किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत, ओडिशा के सभी 30 जिलों में 1800 अभियान चलाए गए और 11,61,568 किसानों को सॉयल हैल्थ कार्डऔर उर्वरकों के संतुलित उपयोग और कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग के बारे में शिक्षित किया गया। किसानों और डीलरों को सावधानीपूर्ण उपयोग विधियों और कीटनाशक अवशेषों के जोखिम को कम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) एवं (ड.): ओडिशा सरकार ने सूचित किया है कि राज्य बरगढ़ और झारसुगुड़ा ज़िलों सहित पश्चिमी ओडिशा में जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और रसायनों पर निर्भरता कम करने के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) का उद्देश्य प्राकृतिक आदानों और पारंपरिक पद्धतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके रसायन मुक्त, पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है ताकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम से कम हो। बलभद्र जैविक खेती मिशन (बीजेसीएम) के तहत, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रशिक्षण, आदान सब्सिडी, प्रमाणन और बाज़ार संपर्क के माध्यम से किसानों का सहयोग करने हेतु जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाता है।

****